

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
देसूरी जिला – पाली

पीठासीन अधिकारी— राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या-01/2017

आरसीएमएस- 2017/00149

तारीख निर्णय- 26/02/2020

प्रार्थीगण :-

- 1- छगनसिंह पुत्र सवाईसिंहजी, आयु- वयस्क,
 - 2- गीता देवी पत्नि सवाईसिंहजी, आयु- वयस्क,
 - 3- भंवरकुंवर पुत्री सवाईसिंहजी, आयु- वयस्क,
 - 4- गजीया कुंवर पुत्री सवाईसिंहजी, आयु- वयस्क,
 - 5- लीला कंवर पुत्री सवाईसिंहजी, आयु- वयस्क,
 - 6- राजकुंवर पत्नि दलपतसिंहजी, आयु- वयस्क,
 - 7- प्रवीणसिंह पुत्र दलपतसिंहजी, आयु- 16 वर्ष,
 - 8- उषा कंवर पुत्री दलपतसिंहजी, आयु- 18 वर्ष, प्रार्थी संख्या-7 नाबालिग
- जरिये कुदरती वलीया (माता) प्रार्थी सं0-6 राजकुंवर के, जातिगण तमाम-
रावणा राजपूत, निवासीगण- नारलाई, तहसील- देसूरी, जिला- पाली
(राज0)

—: विरुद्ध :-

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये-तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

—: प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-136 राज0 भू-राजस्व अधि0 :-

उपस्थिति-

प्रार्थीगण की ओर से- वकील श्री हुकमसिंह सोलंकी।

अप्रार्थी की ओर से- सरकारी पैरोकार




—: निर्णय :-

दिनांक- 26/02/2020

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि- प्रार्थी द्वारा
अन्तर्गत धारा- 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत एक
प्रार्थना-इस



---कमश: पेज- 2 पर.....


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

—कमश: निर्णय पेज... (2)....राजस्व वि०मु०नं०-01/2017प्रार्थीगण-छगनसिंह व अन्य बनाम अप्रार्थी राज्य सरकार अन्तर्गत धारा- 136 आर.एल.आर.एक्ट न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, देसूरी.....

आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि-मौजा सरहद गांव- नारलाई, तहसील- देसूरी मे प्रार्थीगण की पूशतैनी खातेदारी की कब्जा काशत सुदा कृषि भूमि आराजी पुराने खसरा नम्बर- 734 रकबा- 13 बीघा किस्म बारानी प्रथम लगान रूपयां- 8.12 विद्यमान हैं यह आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज सवाईसिंह पुत्र तेजा, जाति- रावणा राजपूत (दरोगा) निवासी- नारलाई की खातेदारी एवं आधिपत्य की थी। सवाईसिंहजी का स्वर्गवास हो चुका है, प्रार्थीगण स्व. सवाईसिंहजी के विधिक वारिसान/उत्तराधिकारीगण है। दौराने सेटलमेंट प्रार्थीगण को मात्र नये खसरा नम्बर- 591 रकबा- 1.18 हैक्टर की ही खातेदारी दी गई जबकि सेटलमेंट विभाग को पुराने इन्द्राज के मुताबिक नया इन्द्राज रकबा- 13 बीघा यानि कि 2.18 हैक्टर की खातेदारी का इन्द्राज करना था व प्रार्थीगण को रकबा- 1.0000 हैक्टर की खातेदारी नही दी गई व प्रार्थीगण को नये खसरा नम्बर- 590 रकबा- 18.88 मे से रकबा- 1.0000 हैक्टर की खातेदारी का इन्द्राज सेटलमेंट विभाग को पुराने इन्द्राज के मुताबिक करना था एवं पुराना नक्शा व नया नक्शा के मुताबिक उप्रार्थीगण के नाम पर रकबा- 1.0000 हैक्टर की खातेदारी सेटलमेंट विभाग ने दर्ज न करके कानूनी भूल की है।

खसरा नम्बर 590 का मिलान क्षेत्रफल भी गत खसरा नम्बर 736 से बनना गलत अंकित किया है व किस्म भी गलत अंकित की है जबकि नक्शे में दर्शित मार्क ए बी सी डी रकबा 1.0000 हैक्टर की भूमि पुराने खसरा नम्बर 734 का भाग है जो प्रार्थीगण की पुरानी खातेदारी की है जिसका राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण के नाम पर सेटलमेन्ट विभाग को इन्द्राज करना था व पुराने इन्द्राज के मुताबिक नये नक्शे में भी सेटलमेन्ट विभाग को इन्द्राज करना था परन्तु ऐसा न करके सेटलमेन्ट विभाग ने कानूनी भूल की है, पुराना नक्शा व नया नक्शा व मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंगन है।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिशल किया गया।

बहस वकूलाय उभय पक्षकार सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नये खसरा नम्बर- 590 रकबा- 18.88 मे से रकबा- 1.0000 हैक्टर को पुराने खसरा नम्बर-734 रकबा-13 बीघा का भाग होना बता कर खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है, जो न्यायालय की राय मे धारा- 136 के अन्तर्गत कानूनन नही दिया जा सकता

—कमश: पेज-3 पर.....



सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

—कमर्चा: निर्णय/आदेश/पेज... (3)....राजस्व वि०मु०नं०-01/2017प्रार्थीगण- छगनसिंह व अन्य बनाम अप्रार्थी राज्य सरकार अन्तर्गत धारा- 136 आर.एल.आर.एक्ट न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, देसूरी.....

है एवं प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में यह स्वीकार करते हुए कि पूर्व में हस्त धारा- 136 राज०भू-राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व विविध प्रकरण संख्या- 21/2011 पेश किया था, जिसका निर्णय दिनांक- 12/12/2011 को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में किया गया है जो कि स्वीकृत एवं निर्विवादित तथ्य है एवं विधि का यह सुस्थापित एवं सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब एक बार प्रार्थीगण द्वारा हस्त धारा-136 के तहत पूर्व में अनुतोष एवं लाभ प्राप्त कर लिया है एवं इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में धारा- 136 के तहत निर्णय आदेश पारित किया जा चुका है, जिससे कानूनन इसी संबंध में हस्त धारा- 136 के तहत दुबारा कोई अनुतोष प्राप्त करने का प्रार्थीगण को अधिकार नहीं है एवं दुबारा न्यायालय द्वारा पुनः निर्णय आदेश कानूनन पारित नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में धारा- 136 के तहत पारित निर्णय आदेश के संबंध में प्रार्थीगण को कोई आपत्ति थी तो प्रार्थीगण उक्त पूर्व आदेश की अपील करनी चाहिए थी।

उपरोक्त विवेचन में न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 136 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने एवं पूर्व में अन्तर्गत धारा- 136 के तहत प्रकरण संख्या- 21/2011 में प्रार्थीगण को अनुतोष प्रदत्त कर दिया गया था जिससे प्रार्थीगण का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 136 राज० भू-राजस्व अधिनियम कानूनन पोषणीय नहीं होकर स्वीकार योग्य नहीं है।


-: आदेश :-

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना-पत्र हस्त धारा- 136 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।




सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ. देसूरी) (पाली)

निर्णय आदेश आज दिनांक- 26/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)